मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

मोदी जी बस करो, बहुत हो गया 2
आप का चरित्र झूठा व दोगला 4
कैसे उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए आरबीआई के काम में हस्तक्षेप 5
चंडीगढ़-विवाद : कृपया जिम्मेदारी से संभालें 6
ईएसआई कॉलेज में सेवाएं बढ़ने लगीं तो जगह छोटी लगने लगी 8

वर्ष 36 | अंक 22 | फरीदाबाद | 10-16 अप्रैल 2022 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

ध्यान भटकाने के लिये लाये 'चंडीगढ़' और 'एसवाईएल'

रोड शो भगवंत मान और स्लीप शो मनोहर लाल खट्टर की नूरां कुश्ती

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

हरियाणा व पंजाब निवासी महंगाई और बेरोजगारी जैसे अति गंभीर मुद्दों से जूझ रहे हैं तो ध्यान भटकाने के लिये इनके सामने 'चंडीगढ़' व 'एसवाईएल' जैसे निरर्थक मुद्दे परोस दिये गये हैं। चंडीगढ़ जहां बना था वहां खड़ा है, वहीं खड़ा रहेगा और जिस काम के लिये बना था उसी के काम आता रहेगा। एसवाईएल पानी का मुद्दा भी बीते 56 साल से पिटारे में बंद करके रखा हुआ है। इसे वक्त जरूरत शासक वर्ग पिटारे से निकाल कर जनता के सामने उछाल देता है।

एक साल तक चले किसान आन्दोलन के दौरान भी बुरी तरह से घबराई-बौखलाई हरियाणा की भाजपा सरकार ने एसवाईएल का मुद्दा पिटारे से निकाल कर हरियाणा पंजाब के किसानों को आपस में लड़ाने का पुरज़ोर प्रयास किया था लेकिन किसान बहकावे में नहीं आये। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस, अकाली व भाजपा का सफ़ाया कर दिये जाने से घबराई भाजपा ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में घुसने से रोकने के लिये उक्त दोनों मुद्दे उछाल दिये हैं। उधर 'आप' को जब इसकी कोई व्यापक काट नज़र नहीं आई तो एक बेहूदा सा प्रस्ताव पंजाब विधान सभा में पास कर दिया। इसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ पंजाब का है।

ध्यान रहे कि पंजाब के सीएम पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने या तो भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई को लेकर थोथी घोषणाएं की हैं या वे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का दुमछल्ला बने हुए अन्य राज्यों (एचपी, गुजरात) में रोड शो करते देखें जा रहे हैं।

इसके मुकाबले में हरियाणा के खट्टर को भी काम मिल गया। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने भी न केवल चंडीगढ़

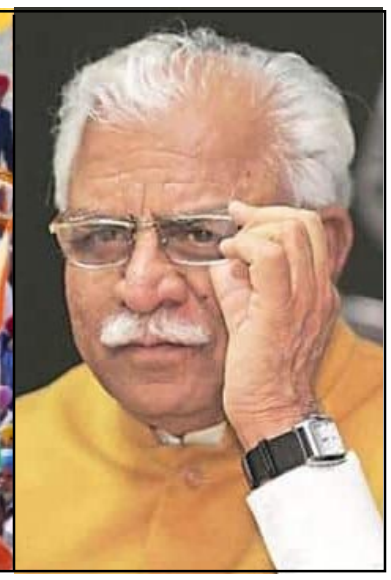

बल्कि एसवाईएल तथा अबोहर-फ़ाजिल्का जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिये। विदित है कि पहली नवम्बर 1966 को पंजाब से अलग होकर बने हरियाणा को ये फिजूल के मुद्दे एक प्रकार से दहेज में मिले थे। बीते 56 साल में दोनों राज्यों में कई बार एक ही पार्टी की सरकारें रह चुकने के बावजूद ये मसले कभी हल न हो पाये और न ही कभी हल हो पायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपनी ऐसी-तैसी करा ली लेकिन मुद्दा जहां का तहां ही रहा।

ऐसे में जागरूक एवं समझदार लोगों को राजनीतिक ठगों के बहकावे में आकर लड़ने-भिड़ने की अपेक्षा अपना आपसी भाईचारा बना कर रखना चाहिये। लड़ने के लिये बढ़ती महंगाई बेरोजगारी सरकारी तंत्र द्वारा लूट आदि जैसे मुद्दे ही काफ़ी हैं। सभी नागरिकों को एक जुट होकर भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों के खिलाफ़ लड़ना चाहिये।

आरटीआई में खुलासा : एडल्ट श्रेणी की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स

चंडीगढ़। पानीपत के आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने कश्मीरी पंडितों पर बनी बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर आरटीआई से मिली सूचना में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मुम्बई (फिल्म सैंसर बोर्ड)के सीनियर रीजनल आफिसर एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नागराज कुलकर्णी ने पीपी कपूर को 22 मार्च की आरटीआई के तहत अपने 1 अप्रैल 2022 के पत्र द्वारा सूचित किया कि द कश्मीर फाइल्स डॉक्यूमेंट्री या कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि ड्रामा श्रेणी की फीचर फिल्म है। कपूर ने इस फिल्म को फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा लाइसेंस देने के समस्त रिकार्ड की कॉपी फाइल नोटिग सहित मांगी थी। इसके जवाब मे कुलकर्णी ने बताया कि यह सूचना सिनेमाटोग्राफी रूल 1983 के रूल 22(4) में नहीं दी जा सकती। इस फिल्म को सर्टीफिकेट देने का ब्यौरा देते हुए फिल्म सैंसर बोर्ड ने बताया कि आवेदक विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म को केन्द्रीय फिल्म सैंसर बोर्ड ने 3 नवम्बर 2011 को ए श्रेणी यानी सिर्फ वयस्को को दिखाने लिए जारी किया था। कपूर ने कहा कि केवल वयस्कों को दिखाने के लिए अडल्ट श्रेणी व ड्रामा श्रेणी की फिल्म को बीजेपी सरकारों द्वारा पूरे देश में प्रोमोट किया गया है।

उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या दुनिया में एडल्ट श्रेणी व ड्रामा श्रेणी की फिल्म को भी प्रोमोट व टैक्स फ्री किया जाता है। इतना ही नहीं इस फिल्म के पोस्टरों पर इसका कहीं उल्लेख भी नहीं किया कि ये फिल्म सिर्फ वयस्को के लिए है। कपूर ने कहा कि इस आरटीआई खुलासे से साफ है कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों को राजनीति का मोहरा बनाकर प्रोमोट की गई है।

वेतन देने को पैसे नहीं, 2212 स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया

चंडीगढ (म.मो.) गतांक में सुधी पाठकों ने पढ़ा था कि हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तरह के कर्मियों की कितनी भारी किल्लत है स्टाफ़ नर्सों, रेड़ियो ग्राफ़रों व लैब टेक्नीशियनों के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद खट्टर सरकार ने इसी सप्ताह 2212 उन स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से हटा दिया जिन्हें कोरोना काल में ठेके पर रखा था। इनमें 1584 स्टाफ़ नर्स, 307 लैब टेक्नीशियन, 197 रेडियोग्राफ़र, 92 फ़ार्मासिस्ट, 20 नर्सिंग सिस्टर, 5 ओटी असिस्टेंट, 5 मेडिकल ऑफ़िसर, 1 परामर्शदाता इत्यादि शामिल हैं।

मानव संसाधनों की कमी से बुरी तरह जूझ रहे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग को जहां हजारों कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के लिये भर्ती निकालनी चाहिये थी, वहीं खट्टर जी ने इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को एक झटके में निकाल बाहर किया। बेशक वे ठेके पर थे, कम वेतन पर उनसे काम लिया जा रहा था, फ़िर भी वे हर तरह से स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर रहे थे। उन्हें

राज्य भर में अस्पतालों के स्टाफ की स्थिति क्या है ?

		स्वीकृत पद	तैनात	रिक्त	
डॉक्टर	-	4881	4063	818	
स्टाफ नर्स	-	4399	2168	2231	50 %
हेल्थ वर्कर	-	6539	5190	1348	
लैब तकनीकी	-	1260	545	715	56 %
फ़ार्मासिस्ट	-	1050	680	370	
रेड़ियोग्राफर	-	314	95	219	69 %
ऑप्थो सहायक	-	190	75	115	60 %

नियमित करने की बजाय खट्टर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जाहिर है इससे खट्टर सरकार का करोड़ों रुपया बच जायेगा। लेकिन यह सोचनेवाला कोई नहीं है कि उन सैंकड़ों स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीज़ों को क्या मिल पायेगा जहां बिल्डिंग तो है लेकिन चिकित्सा सेवा देने वाला कोई नहीं।

शासन-प्रशासन चलाने वालों को इन सब बातों से क्या लेना-देना ? उन्हें तो जब इलाज कराना होता है तो एक से बढ़िया एक निजी पंचतारा अस्पताल उपलब्ध हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की जब टांग टूटी थी तो वे अपने किसी सरकारी अस्पताल में न जाकर अम्बाला से मोहाली के एक निजी अस्पताल गये थे। जब उन्हें कोरोना हुआ तो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व रोहतक मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा को देखते हुए गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में आकर टिके थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने मातहत अस्पतालों का कोई सुधार करने की जरूरत न समझी। शायद, भाजपा सरकार समझती है कि अच्छे अस्पताल व स्कूल आदि बनाने से जनता वोट नहीं देती; वोट तो जनता को धर्म व जाति के नाम पर बेवकूफ़ बना कर ही लिये जा सकते हैं।